आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) इनमें से कितने मामलों को स्वीकार कर लिया गया था और कितने मामलों को अस्वीकार कर दिया गया था;

(ग) क्या मैसर्स कन्सोलिडेटिड स्टील एंड एलायज लिमिटेड को उनसे पचास लाख रुपये जमा करा लेने के बाद भी उन्हें पुनः वित्त पोषण का लाभ नहीं दिया जा सका;

(घ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निदेशों के बावजूद सेंट्रल बैंक द्वारा उक्त फर्म को ब्याज सहित राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त फर्म को जमा राशि पर ब्याज की राशि दिलाने एवं इसी प्रकार के अन्य मामलों के निपटान के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (वाइफर) ने बताया है कि उसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सीका) की धारा 15(1) के तहत 272 संदर्भ मिले थे, जिनमें से 188 मामले पंजीकृत किए गये थे तथा 84 मामलों में पंजीकरण नहीं किया गया था।

(ग) से (ङ) सीका के उपबंधों के अनुसार वाइफर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की थी। वाइफर ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को निदेश दिया था कि कंपनी को 50 लाख रुपए लौटा दें। तथापि, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने वाइफर के निर्देशों के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (आइफर) में अपील दायर की थी। आइफर ने अपील रद्द कर दी थी। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि वाइफर के निदेशानुसार दिसम्बर 1997 में कंपनी को 50 लाख रुपए वापस कर दिए गए थे। बैंक ने यह भी बताया है कि चूंकि धनराशि "पुनर्ग्रहणाधिकार रहित खाते" में रखी गई थी, न कि "ब्याज वाले जमा खाते" में, अतः ब्याज देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

CBI Enquiry against Ganpati Exports

3770. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any inquiry had been conducted by CBI and Directorate of Enforcement in respect of Calcutta based Ganpati Exports and Pashupati Acreylices, New Delhi;

(b) if so, the details thereof togetherwith the amount involved therein;

(c) whether action has been taken on the said report; and

(d) if so, the names of persons involved in the racket?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) to (d) Investigations have been taken up by the Enforcement Directorate against M/s. Ganpati Exports, Calcutta and M/s. Pashupati Acrylon Ltd., New Delhi for suspected violation of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

सहारा ग्रुप के पास जमा धनराशि

3771. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1998 के "दी इकोनामिक टाइम्स" में "आरबीआई प्रोब्स विग राइस इन सहारा डिपोजिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) और (ख) समाचार मद में बताया गया है कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कार्पोरेशन लिमिटेड की जमाराशियों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत संवितरित निधियों के कारण है जो कंपनी को जमाराशियों के रूप में प्राप्त हो रही हैं।

(ग) अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनी, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कार्पोरेशन लि० द्वारा धारित प्रतिभूतियों का केवल प्रत्यक्ष सत्यापन कराया था। अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनियों सहित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं की निधियों के स्रोत की किसी प्रकार की जांच का कार्य,

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में निहित शक्तियों से परे है। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से यह आशा की जाती है कि यह सुनिश्चित करें कि परिसंपत्तियों का सृजन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया है।

Shortfall in Printing of Notes

3772. SHRI SOLIPETA RAMCHANDRA REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether RBI printing units in the country are printing notes to full capacity;

(b) if so, the reasons for shortfall in the country; and

(c) if not, the steps proposed to utilise the full capacity to stop import of currency notes and to meet the shortage?

MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) The RBI printing units at Mysore and Salboni are presently having plant and machinery for one line of production. Present installed capacity on the basis of one shift at Mysore and double shift at Salboni, is 1800 million pieces against which the production was 1761 million pieces during the year 1997-98.

(b) Before the RBI printing presses commenced production, the currency notes were printed only at Currency Note Press, Nasik and Bank Note Press, Dewas. These two printing presses together are able to meet only about 35% of the demand for fresh notes by RBI.

(c) When all the lines of machines at RBI printing presses come into full production, by end of the year, the presses would be able to produce 4770 million pieces of note each. Besides the Government note-printing presses at Nasik and Dewas also being modernised. After completion of the modernisation programme by end of this year thier production capacity will also be increased from 7775 million pieces to 8300 million pieces per year. In order to meet the shortage situation Government has also permitted RBI to import printed notes of 3600 million pieces, as a one time measure.

Accumulation of Tax arrears

3773. DR. JAGANNATH MISRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a huge amount of tax arrears is accumulating in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reasons therefor both in respect of direct and indirect taxes; and

(d) the steps taken by Government to solve the problem and achievement made so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Cases of irregularities in State Bank of Indore

3774. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to answer to Starred Question 165 given in the Rajya Sabha on 3rd December, 1996 and state:

(a) whether the cases of the Union Leaders/employees found guilty of misusing the house loan advance and on whom penalty of withholding of 2/6 increments was imposed been settled and punishments reduced by the Bank;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the enquiry against the officer at Gwalior (staying for the last 8 years) has since been completed; and

(d) if so, the outcome thereof and the action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (d) The disciplinary proceedings initiated against the employees in the public sector banks are governed by the well-established